



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2014—पौष 27, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-793-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. संजय गोयल,
आयएस., कलेक्टर, जिला अशोकनगर को दिनांक 23 दिसम्बर
2013 से 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश
स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21, 22
दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने
की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. संजय गोयल की अवकाश अवधि में श्री उपेन्द्र नाथ
शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अशोकनगर को
अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी
आदेश तक, कलेक्टर, जिला अशोकनगर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. संजय गोयल को अस्थायी रूप
से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अशोकनगर के
पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. संजय गोयल द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर का
कार्यभार ग्रहण करने पर श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा कलेक्टर, जिला
अशोकनगर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. संजय गोयल को अवकाश वेतन एवं
भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व
मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. संजय गोयल
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-831-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री स्वाती मीणा, आयएस., कलेक्टर, जिला सीधी को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) सुश्री स्वाती मीणा की अवकाश अवधि में श्री अनिल खरे, अपर कलेक्टर, सीधी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सीधी का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री स्वाती मीणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सीधी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) सुश्री स्वाती मीणा द्वारा कलेक्टर, जिला सीधी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल खरे, कलेक्टर, जिला सीधी के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में सुश्री स्वाती मीणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री स्वाती मीणा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-917-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सौरभ कुमार सुमन, आयएस., सहायक कलेक्टर, जिला-जबलपुर को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सौरभ कुमार सुमन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला-जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सौरभ कुमार सुमन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सौरभ कुमार सुमन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-547-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएस., विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश, नई दिल्ली को दिनांक 26 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक, 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-726-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, आयएस., आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में आयुक्त, जनसंपर्क का प्रभार श्री मनोज श्रीवास्तव, आयएस., प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग को तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार श्री अनुराग श्रीवास्तव, भावसे आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज श्रीवास्तव, आयुक्त जनसंपर्क एवं श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-743-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. बी. सिंह, आयएस., कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक, छह: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 दिसम्बर 2013 एवं 29 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री एस. बी. सिंह की अवकाश अवधि में श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे कलेक्टर, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. बी. सिंह द्वारा कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निशांत वरवड़े कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-792-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल, आयएस., कलेक्टर, जिला श्योपुर को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 15 जनवरी 2014 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल की अवकाश अवधि में श्री एच. पी. वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्योपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला श्योपुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल द्वारा कलेक्टर, जिला श्योपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. पी. वर्मा कलेक्टर, जिला श्योपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-807-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. पी. राही, आयएस., अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. राही को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. पी. राही को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. राही अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-897-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. के. जैन, आयएस., कलेक्टर, जिला रायसेन को दिनांक 26 दिसम्बर 2013 से 3 जनवरी 2014 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री जे. के. जैन की अवकाश अवधि में श्री राधेश्याम अगस्थी, अपर कलेक्टर, रायसेन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रायसेन का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रायसेन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जे. के. जैन द्वारा कलेक्टर, जिला रायसेन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम अगस्थी कलेक्टर, जिला रायसेन के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जे. के. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. के. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-713-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण पाण्डेय, आयएस., कमिशनर उज्जैन संभाग को दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अरूण पाण्डेय की अवकाश अवधि में श्री बी. एम. शर्मा, भाप्रसे कलेक्टर, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिशनर, उज्जैन संभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण पाण्डेय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिशनर, उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अरूण पाण्डेय द्वारा कमिशनर, उज्जैन संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एम. शर्मा कमिशनर, उज्जैन संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अरूण पाण्डेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-830-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संकेत भोंडवे शांताराम, भाप्रसे मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, भोपाल को दिनांक 28 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संकेत भोंडवे शांताराम, को मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संकेत भोंडवे शांताराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री संकेत भोंडवे शांताराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-884-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती तन्वी सुन्दरियाल बहुगुणा, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिंदवाड़ा को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2013 द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

(2) श्रीमती तन्वी सुन्दरियाल बहुगुणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रत्नाकर झा, राप्रसे अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अवकाश अवधि में प्रभार श्री रत्नाकर झा, राप्रसे से अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा के स्थान पर अब, श्री राजेन्द्र राय, संयुक्त कलेक्टर, छिंदवाड़ा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) श्रीमती तन्वी सुन्दरियाल बहुगुणा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिंदवाड़ा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेन्द्र राय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-829-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नागरगोजे मदन विभीषण, आयएस., कलेक्टर, जिला मुरैना को दिनांक 2 से 15 जनवरी 2014 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री नागरगोजे मदन विभीषण की अवकाश अवधि में श्री आशीष गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर (विकास) मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला मुरैना का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नागरगोजे मदन विभीषण द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष गुप्ता कलेक्टर, जिला मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-817-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राहुल जैन, आयएस., कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 6 से 10 जनवरी 2014 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जनवरी 2014 एवं 11, 12 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होशंगाबाद को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. ई-5-632-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुपम राजन, आयएस, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 24 से 28 दिसम्बर 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2014

क्र. ई-1-394-2013-5-एक.—श्री आई.सी.पी. केशरी, भाप्रसे (1988) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (आवासीय आयुक्त कार्यालय में संलग्न) तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश नई दिल्ली पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री आई. सी. पी. केशरी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश नई दिल्ली के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2014

क्र. ई-5-532-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा संसदीय कार्य जनशिकायत निवारण विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2013 द्वारा दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2013 तक, पन्द्रह दिन का

अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था। उक्त अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगीं।

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2014

क्र. ई-5-693-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण तिवारी, आयएस, कमिशनर, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 एवं 31 दिसम्बर 2013 का स्थानीय अवकाश एवं दिनांक 29 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिशनर, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अरूण तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री अरूण तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-787-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएस, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 2 जनवरी 2014 से 1 फरवरी 2014 तक इकतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राजकुमारी खन्ना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-929-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री प्रतिभा पाल, आयएस, सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 3 जनवरी 2014 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा पाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री प्रतिभा पाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि सुश्री प्रतिभा पाल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अँटोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 11-29-2013-एक-9.—राज्य शासन, एतद्वारा, प्रदेश में समस्त निगमों, मण्डलों, प्राधिकरणों, समितियों, परिषदों आदि में राज्य शासन द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्यों के किये गये मनोनयन (केवल इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

उक्त आदेश अनुसार प्रदेश के समस्त निगमों, मण्डलों, प्राधिकरणों, समितियों, परिषदों आदि संस्थाओं के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/संचालकों/सदस्यों आदि का कार्यकाल इस आदेश के जारी होने की तिथि से स्वमेव समाप्त माना जावेगा। नवीन मनोनयन/नियुक्ति होने तक उक्त प्रभार के संबंध में यथा उचित नियम/अधिनियम/निर्देश अनुसार संबंधित प्रशासकीय विभाग समन्वय में आदेश प्राप्त करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2014

क्र. एफ. 11-29-2013-एक-9.—समसंख्यक पत्र दिनांक 23 दिसम्बर 2013 द्वारा निगम/मण्डलों/प्राधिकरणों/समितियों/परिषदों में किये गये मनोनयन/नियुक्तियाँ समाप्त कर दी गई हैं। पुनः मनोनयन/नियुक्ति होने तक इन निगम, मण्डल, प्राधिकरण, समिति एवं परिषद् के प्रशासकीय वित्तीय एवं सामान्य कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही कृपया सुनिश्चित करें :—

1. निगम-मण्डल के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के भारसाधक माननीय मंत्रीजी को सौंपा जाये।
2. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यभार यथास्थिति क्रमशः संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर को सौंपा जाये।
3. प्रशासकीय विभाग अन्तर्गत गठित समिति/परिषद् के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को सौंपा जाये।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2014

फा. क्र. 4-ए-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(1) एवं 3(5) के अन्तर्गत निम्न सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि अथवा आगामी आदेश होने तक (जो भी पहले हो) एतद्वारा कुटुम्ब न्यायालय में नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक सदस्य का नाम	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि
(1)	(2)	(3)
1.	कु. प्रतिभा रत्नपारखी	31-12-2014
2.	श्री श्याम कुमार मण्डलोई	11-3-2015
3.	श्री बलदेव सिंह परमार	30-8-2015
4.	श्री कैलाश चन्द्र गर्ग	24-10-2015
5.	श्री उल्लास बाबट	28-12-2015
6.	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव	31-12-2015

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 (5) के अन्तर्गत होगा।

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014

फा. क्र. 4-ए-2002-इक्कीस-ब(एक).**शुद्धिपत्र**—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जनवरी 2014 की तालिका में सरल क्र. 3 पर “श्री बलदेव सिंह परमार” के स्थान पर “श्री बलबीर सिंह परमार” एवं सरल क्र. 5 पर “श्री उल्लास बाबट” के स्थान पर “श्री उल्लास बापट” पढ़ा जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्र. एफ. 13-6-2010-बत्तीस-1.—सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-29-2013-एक-9, दिनांक 23 दिसम्बर 2013 द्वारा निगमों/मण्डलों/प्राधिकरणों/समितियों/परिषदों आदि में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्यों का किये गये नियुक्ति/मनोनयन को निरस्त किया गया है।

2. अतः सामान्य प्रशासन विभाग का उक्त आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2013 मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जारी किये गये आदेश के अनुरूप अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य के पद रिक्त मान्य किये जाते हैं।

3. मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री कैलाश विजयवर्गीय, मान. मंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, आगामी आदेश तक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के पद पर नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश एस. शेटे, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश)—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-49-12-तीन-39.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जुलाई, 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, बड़वानी, जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में सुश्री राधा पटेल, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त, 2012 तक, सुश्री राधा पटेल को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री राधा पटेल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री राधा पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2012 को जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री राधा पटेल से जवाब (लिखित

अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी सुश्री राधा पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री राधा पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च 2013 के संलग्न परिशिष्ट-36 की टिप्पणी में प्रतिवेदित किया कि—अभ्यर्थी सुश्री राधा पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा व्यय लेखा वर्तमान तक पेश नहीं किया गया और न ही कोई अभ्यावेदन पत्र दिया गया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री राधा पटेल को दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। अभ्यर्थी सुश्री राधा पटेल सुनवाई में उपस्थित नहीं हुईं, जबकि अभ्यर्थी सुश्री राधा पटेल को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2013 की तामिली विहित समयावधि में दिनांक 20 अक्टूबर 2013 को कराई जा चुकी थी।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री राधा पटेल द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री राधा पटेल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् बड़वानी, जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-06-13-तीन-51.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जनवरी, 2013 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, राघौगढ़ विजयपुर, जिला गुना के आम निर्वाचन में श्री गोपाल, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जनवरी 2013 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 9 एवं 10 फरवरी, 2013 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 11 फरवरी 2013 तक, श्री गोपाल को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी गुना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गुना के पत्र दिनांक 15 फरवरी, 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री गोपाल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री गोपाल को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 7 मार्च, 2013 को जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र में श्री गोपाल से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री गोपाल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 मार्च 2013 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 31 मार्च 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। अभ्यर्थी

श्री गोपाल द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में अपना अभ्यावेदन आयोग को प्रस्तुत किया गया। आयोग के पत्र दिनांक 9 मई 2013 द्वारा अभ्यावेदन की स्वीकार्यता किये जाने के संबंध में कलेक्टर गुना से उनका अभिमत चाहा गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला गुना से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 16 सितम्बर 2013 में प्रतिवेदित किया कि अभ्यर्थी श्री गोपाल के अभ्यावेदन में अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ से वर्णित तथ्यों की सत्यता/विश्वसनीयता का परीक्षण कराया गया, जिसमें वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यर्थी ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री गोपाल को दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। किन्तु अभ्यर्थी श्री गोपाल आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2013 की तामिली अभ्यर्थी श्री गोपाल को विहित समयावधि में दिनांक 29 अक्टूबर 2013 को कराई जा चुकी थी।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री गोपाल द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने में कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री गोपाल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् राघौगढ़ विजयपुर, जिला गुना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहिंत (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-07-12-तीन-53.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है

कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जुलाई, 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा के आम निर्वाचन में श्री प्यारू भाई रियाज अली अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगरपालिका परिषद्, जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त, 2012 तक, श्री प्यारू भाई रियाज अली को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छिन्दवाड़ा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छिन्दवाड़ा के पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री प्यारू भाई रियाज अली द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री प्यारू भाई रियाज अली को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 नवम्बर 2012 को जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री प्यारू भाई रियाज अली को नोटिस दिनांक 5 जनवरी 2013 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 20 जनवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर छिन्दवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 8 अगस्त 2013 में लेख किया कि “कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उक्त अभ्यर्थी द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।”

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री प्यारू भाई रियाज अली को दिनांक 12 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया। किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए, जबकि श्री प्यारू भाई रियाज अली को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 5 सितम्बर 2013 की तामीली नियत समयावधि में दिनांक 22 सितम्बर 2013 को कराई जा चुकी थी।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री प्यारू भाई रियाज अली को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् जुन्नारदेव, का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-07-12-तीन-54.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जुलाई, 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा के आम निर्वाचन में श्री रामकुमार शर्मा, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगरपालिका परिषद्, जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त, 2012 तक, श्री रामकुमार शर्मा को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छिन्दवाड़ा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन

अधिकारी छिन्दवाड़ा के पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रामकुमार शर्मा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री रामकुमार शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 नवम्बर 2012 को जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री रामकुमार शर्मा के नोटिस तामीली की प्रति पर अंकित है कि उनके घर बार-बार सम्पर्क करने पर मालूम हुआ कि श्री रामकुमार शर्मा बाहर गये हैं इसलिये दिनांक 18 जनवरी 2013 को श्री रामकुमार शर्मा के घर नोटिस चस्पा किया गया। अतः उनको दिनांक 2 फरवरी, 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर छिन्दवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 8 अगस्त 2013 में लेख किया कि “कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।”

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री रामकुमार शर्मा को आयोग में दिनांक 12 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया। अभ्यर्थी उक्त दिनांक को आयोग में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। अभ्यर्थी द्वारा समक्ष में बताया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखों की छायाप्रतियां, जिला स्तर पर विलम्ब से प्रस्तुत की थीं।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा विलम्ब से व्यय लेखों की छायाप्रतियां प्रस्तुत करने के संबंध में कोई ठोस प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रामकुमार शर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् जुनारदेव, का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहिंत (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-11-07-तीन-56.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह नवम्बर, 2007 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, कोलार, जिला भोपाल के निर्वाचन में श्रीमती रूपादास, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगरपालिका परिषद्, कोलार, जिला भोपाल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 नवम्बर, 2007 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 दिसम्बर, 2007 तक, इन्हें निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पत्र क्र. 27/स्था.निर्वा./08, दिनांक 22 जनवरी, 2008 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती रूपादास द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती रूपादास को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 8 फरवरी 2008 जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्रीमती रूपादास को सूचना पत्र की तामीली दिनांक 13 जुलाई, 2011 को उनके पति के माध्यम से कराई गई।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 3 मार्च, 2012 को अभ्यर्थी **श्रीमती रूपादास** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 3 फरवरी 2012 की तामीली कलेक्टर भोपाल के माध्यम से दिनांक 29 फरवरी 2012 को कराई गई। अभ्यर्थी के पति श्री बी. एल. दास व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 3 मार्च, 2012 को उपस्थित हुए। उनके द्वारा अभ्यर्थी **श्रीमती रूपादास** का अभ्यावेदन एवं मूल निर्वाचन व्यय लेखा मय रसीद के सुनवाई दिनांक को प्रस्तुत किया गया। अभ्यर्थी ने अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा व्यय संबंधी व्यौरों की छायाप्रतियां जमा की गई थीं। अभ्यर्थी **श्रीमती रूपादास** ने पहली बार एक स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी, जिसके कारण खर्च जमा करने में चूक हुई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती रूपादास** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद् कोलार, जिला भोपाल** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-28-12-तीन-58.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जुलाई, 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, **सैलाना, जिला रतलाम** के आम निर्वाचन में **श्री कुलदीप सिंह “बाबला”** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त, 2012 तक, **श्री कुलदीप सिंह “बाबला”** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम के पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री कुलदीप सिंह “बाबला”** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री कुलदीप सिंह “बाबला”** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र में **श्री कुलदीप सिंह “बाबला”** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी **श्री कुलदीप सिंह “बाबला”** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 15 नवम्बर को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 30 अक्टूबर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था। आयोग द्वारा **श्री कुलदीप सिंह “बाबला”** को कारण बताओ सूचना पत्र तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रतलाम से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 22 जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया कि कारण बताओ नोटिस तामीली के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक अभ्यर्थी **श्री कुलदीप सिंह “बाबला”** द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्री कुलदीप सिंह “बाबला”** को दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। अभ्यर्थी **श्री कुलदीप सिंह “बाबला”** सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। जबकि अभ्यर्थी **श्री कुलदीप सिंह “बाबला”** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2013 की तामीली विहित समयावधि में कराई जा चुकी थी।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री कुलदीप सिंह “बाबला” द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री कुलदीप सिंह “बाबला” को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् सैलाना, जिला रतलाम का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहिता (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्र. 121-453-अका-विपप्र-2013-संशोधन.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-सिविल, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-केवल अधिनियम), सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 2684-452-अका-विपप्र-2013, दिनांक 16 अप्रैल 2013 को जारी की गई थी, में भोपाल संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री सातन राव देशमुख, राजस्व निरीक्षक अंकित है, के स्थान पर अब श्री सातन राव देशमुख, नायब तहसीलदार पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. 1-2013-MNV/R-कोला.नियं.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी-अनुभाग) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 44-10-2013-दो-सी-1, भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2013 द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आवेदन क्रमांक 8-13 में पारित निर्णय दिनांक 8 अक्टूबर 2013 के तारतम्य में जिले के अन्तर्गत शांत क्षेत्र (Silence Zone) अधिसूचित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। अतः, मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं मदन कुमार, जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना, मुरैना जिले के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबन्धित क्षेत्र (Silence Zone) घोषित करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि निम्न शांत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगण किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल, लाउड स्पीकर, साउण्ड बाक्स आदि शामिल हैं का उपयोग नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगण ऐसा करते पाया जाता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15(1)(2) एवं 16 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

क्र. (1)	स्थान का नाम (2)	घोषित क्षेत्र की सीमा (3)	कोलाहल प्रतिबंधित अवधि (4)
1	कमिश्नर, कार्यालय	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.50 बजे तक
2	जिला एवं सत्र न्यायालय, मुरैना	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
3	कलेक्टर कार्यालय, मुरैना	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.50 बजे तक
4	जिला चिकित्सालय, मुरैना	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे
5	शिक्षा नगर, रोड मुरैना	सम्पूर्ण क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
6	शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरैना	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
7	शासकीय चिकित्सालय, पोरसा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे
8	कार्यालय तहसीलदार, पोरसा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
9	शास. कन्या उ. मा. वि./बा. मा. वि., पोरसा.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
10	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बाह.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
11	शास. उ. मा. वि., बानमोर	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)
12	न्यायालय परिसर एम. एस. रोड, जौरा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
13	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
14	कार्यालय तहसीलदार, जौरा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
15	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जौरा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे
16	शासकीय महाविद्यालय, जौरा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
17	शास. बा. उ. मा. वि., जौरा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
18	कार्यालय तहसीलदार, कैलारस	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
19	शास. बालक उ. मा. वि., कैलारस	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
20	सामुदायिक स्वा. केन्द्र, झुण्डपुरा	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे
21	शास. मा. एवं हाईस्कूल वार्ड क्र. 8, झुण्डपुरा.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
22	न्यायालय क्षेत्र, सबलगढ़	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
23	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
24	शास. नेहरू महाविद्यालय, सबलगढ़	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 08.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
25	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सबलगढ़	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा.

मदन कुमार, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. 304-स्था.निर्वा.-मण्डी निर्वा-2014.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर सीहोर, मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम 2010 के अंतर्गत सीहोर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र.	मण्डी समिति का नाम	नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	सांसद/विधायक जिनके प्रतिनिधि नियुक्त किये गये हैं
(1)	(2)	(3)	(4)
1	04-आष्टा	श्री बापूलाल मालवीय, निवासी ग्राम अरोलिया, तह. आष्टा, जिला सीहोर.	सांसद प्रतिनिधि
2	06-इछावर	श्री राधेश्याम कबाड़ी, नि. इछावर, तह. इछावर, जिला-सीहोर.	सांसद प्रतिनिधि
3	07-श्यामपुर	श्री रामनिवास पचौरी, नि. ग्राम बाजार गांव पो. बरखेड़ा हसन, तह. श्यामपुर, जिला-सीहोर.	सांसद प्रतिनिधि
4	09-बकतरा	श्री रघुवीर सिंह चौहान, नि. ग्राम मछबाई, तह. बुधनी, जिला सीहोर.	विधायक प्रतिनिधि

कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

नरसिंहपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

अनुसूची

प्र. क्र. 15-अ-82-वर्ष 2012-13 पत्र-क्र. 590-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गोटेगांव
(ग) ग्राम—बांसखेड़ा नं.बं. 74,
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.194 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
201/1, 201/2	0.105
205/1	0.034
200/1	0.055
योग . .	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बांसखेड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 069-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम—कोहनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.075 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
61	0.254	निजी भूमि
74/2	0.012	निजी भूमि
75/2	0.015	निजी भूमि
74/1	0.012	निजी भूमि
75/1	0.016	निजी भूमि
80	0.025	निजी भूमि
73/1	0.350	निजी भूमि
81	0.276	निजी भूमि
83/1	0.040	निजी भूमि
82/1	0.070	निजी भूमि
280	0.378	निजी भूमि
286	0.061	निजी भूमि
283	0.196	निजी भूमि
288/1	0.031	निजी भूमि
310	0.029	निजी भूमि
288/2ख	0.161	निजी भूमि
288/2क	0.002	निजी भूमि
309	0.147	निजी भूमि
योग . .	2.075	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—डोभा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 083-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पन्ना

(ग) ग्राम—इटवांकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.443 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1508	0.251	निजी भूमि
1509	0.304	निजी भूमि
1510/2	1.000	निजी भूमि
1506	0.320	निजी भूमि
1510/1	0.133	निजी भूमि
1531/1	0.030	निजी भूमि
1530	0.035	निजी भूमि
1505	0.093	निजी भूमि
1504	0.101	निजी भूमि
1511	0.110	निजी भूमि
1512	0.010	निजी भूमि
1513	0.030	निजी भूमि
1517	0.120	निजी भूमि
1503	0.129	निजी भूमि
1518/1	0.100	निजी भूमि
1502	0.400	निजी भूमि
1501	0.263	निजी भूमि
1496	0.010	निजी भूमि
1497	0.142	निजी भूमि
1498	0.093	निजी भूमि
1499/2	0.109	निजी भूमि
1471	0.105	निजी भूमि
1472	0.024	निजी भूमि
1473/1	0.058	निजी भूमि
1473/2	0.058	निजी भूमि
1473/3	0.058	निजी भूमि
1500	0.194	निजी भूमि
1499/3	0.043	निजी भूमि
1499/1	0.083	निजी भूमि
1480	0.154	निजी भूमि
1481	0.057	निजी भूमि
1482	0.575	निजी भूमि
1483	0.069	निजी भूमि
1488/1	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
1454/1	0.013	निजी भूमि
1457	0.061	निजी भूमि
1451	0.040	निजी भूमि
1452	0.040	निजी भूमि
1453	0.024	निजी भूमि
1454/2	0.011	निजी भूमि
1455	0.045	निजी भूमि
1456/1	0.050	निजी भूमि
1458/1	0.016	निजी भूमि
1462/1	0.020	निजी भूमि
1463/1	0.020	निजी भूमि
1464/1	0.015	निजी भूमि
1465/1	0.015	निजी भूमि
1466/1	0.055	निजी भूमि
1467/1	0.036	निजी भूमि
1468/1	0.029	निजी भूमि
1475/1	0.040	निजी भूमि
1456/2	0.051	निजी भूमि
1458/2	0.016	निजी भूमि
1462/2	0.020	निजी भूमि
1463/2	0.020	निजी भूमि
1464/2	0.015	निजी भूमि
1465/2	0.015	निजी भूमि
1466/2	0.054	निजी भूमि
1467/2	0.037	निजी भूमि
1468/2	0.028	निजी भूमि
1475/2	0.041	निजी भूमि
1459	0.089	निजी भूमि
1460	0.049	निजी भूमि
1469	0.081	निजी भूमि
1474	0.170	निजी भूमि
1470	0.121	निजी भूमि
1476	0.113	निजी भूमि
1479	0.105	निजी भूमि
1477	0.109	निजी भूमि
1478	0.328	निजी भूमि
1448	0.040	निजी भूमि
1461	0.060	निजी भूमि
1450/1	0.080	निजी भूमि
योग ..		7.443

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—डोभा तालाब योजना के अन्तर्गत बेस्ट वियर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 095-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—धवारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—55.68 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)			
228	0.19	निजी भूमि	642	0.06	निजी भूमि
229	0.55	निजी भूमि	282	0.01	निजी भूमि
231	0.24	निजी भूमि	285	0.30	निजी भूमि
354	0.26	निजी भूमि	289	0.14	निजी भूमि
355	0.08	निजी भूमि	293/1	0.14	निजी भूमि
505	0.14	निजी भूमि	300/1	0.02	निजी भूमि
506	0.06	निजी भूमि	293/2	0.07	निजी भूमि
507	0.10	निजी भूमि	294/1	0.04	निजी भूमि
647	0.15	निजी भूमि	295/1	0.05	निजी भूमि
648	0.10	निजी भूमि	300/2	0.30	निजी भूमि
649	0.18	निजी भूमि	294/2	0.20	निजी भूमि
651	0.30	निजी भूमि	295/2	0.14	निजी भूमि
652	0.29	निजी भूमि	529/2	1.48	निजी भूमि
653	0.30	निजी भूमि	558	0.06	निजी भूमि
654	0.11	निजी भूमि	296	0.30	निजी भूमि
655	0.23	निजी भूमि	297	0.41	निजी भूमि
755	0.30	निजी भूमि	298	0.19	निजी भूमि
756	0.15	निजी भूमि	299	0.18	निजी भूमि
757	0.06	निजी भूमि	301	0.15	निजी भूमि
232	0.12	निजी भूमि	303	0.32	निजी भूमि
233	0.05	निजी भूमि	304	0.23	निजी भूमि
234	0.27	निजी भूमि	306	0.23	निजी भूमि
235	0.26	निजी भूमि	307	0.21	निजी भूमि
279	0.35	निजी भूमि	408	0.21	निजी भूमि
353	0.11	निजी भूमि	410	0.18	निजी भूमि
468	0.04	निजी भूमि	411	0.06	निजी भूमि
474	0.53	निजी भूमि	413	0.30	निजी भूमि
476	0.40	निजी भूमि	414	0.22	निजी भूमि
			523	0.14	निजी भूमि
			531	0.27	निजी भूमि
			532	0.20	निजी भूमि
			541	0.09	निजी भूमि
			543	0.13	निजी भूमि
			679	1.06	निजी भूमि
			308	0.35	निजी भूमि
			309	0.30	निजी भूमि
			310	0.47	निजी भूमि
			680	1.17	निजी भूमि
			311	1.27	निजी भूमि
			312	0.59	निजी भूमि
			314	0.24	निजी भूमि
			315	0.11	निजी भूमि
			316	0.01	निजी भूमि
			321	0.05	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
322	0.07	निजी भूमि	459	0.23	निजी भूमि
334	0.32	निजी भूमि	461	0.36	निजी भूमि
337	0.32	निजी भूमि	487	0.38	निजी भूमि
339	0.42	निजी भूमि	488	0.11	निजी भूमि
340	0.34	निजी भूमि	460	0.10	निजी भूमि
341	0.03	निजी भूमि	485	0.05	निजी भूमि
342	0.14	निजी भूमि	486	0.21	निजी भूमि
473	0.26	निजी भूमि	495	0.16	निजी भूमि
475	0.11	निजी भूमि	462	0.64	निजी भूमि
477	0.23	निजी भूमि	465	1.81	निजी भूमि
513	0.11	निजी भूमि	469	0.13	निजी भूमि
515	0.29	निजी भूमि	494/1	0.39	निजी भूमि
516	0.32	निजी भूमि	557	0.18	निजी भूमि
517	0.13	निजी भूमि	704	0.02	निजी भूमि
528	0.10	निजी भूमि	466	0.85	निजी भूमि
338	0.23	निजी भूमि	467	0.38	निजी भूमि
618/1	0.05	निजी भूमि	470/1	0.20	निजी भूमि
621/2	0.15	निजी भूमि	483/2/क	0.40	निजी भूमि
343	0.22	निजी भूमि	470/2	0.18	निजी भूमि
344	0.14	निजी भूमि	483/2/ख	0.80	निजी भूमि
345	0.24	निजी भूमि	478/2	0.70	निजी भूमि
346	0.13	निजी भूमि	481	0.12	निजी भूमि
347	0.33	निजी भूमि	482	0.02	निजी भूमि
348	0.16	निजी भूमि	489	0.25	निजी भूमि
349	0.11	निजी भूमि	490	0.16	निजी भूमि
350	0.15	निजी भूमि	491	0.10	निजी भूमि
351	0.29	निजी भूमि	492	0.11	निजी भूमि
352	0.17	निजी भूमि	493	0.24	निजी भूमि
684	0.30	निजी भूमि	512	0.26	निजी भूमि
399	0.12	निजी भूमि	494/2	0.16	निजी भूमि
400	0.14	निजी भूमि	499	0.20	निजी भूमि
404	0.02	निजी भूमि	497	0.87	निजी भूमि
406	0.12	निजी भूमि	556	0.04	निजी भूमि
407	0.12	निजी भूमि	500	0.10	निजी भूमि
415	0.21	निजी भूमि	502	0.04	निजी भूमि
416	0.14	निजी भूमि	503	0.06	निजी भूमि
677	0.04	निजी भूमि	504	0.03	निजी भूमि
418	0.19	निजी भूमि	526	0.29	निजी भूमि
419	1.03	निजी भूमि	527	0.32	निजी भूमि
422	0.48	निजी भूमि	758	0.15	निजी भूमि
443	0.18	निजी भूमि	759	0.02	निजी भूमि
446	0.05	निजी भूमि	514	0.10	निजी भूमि
455	1.30	निजी भूमि	519	0.56	निजी भूमि
456	1.20	निजी भूमि	520	0.33	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
518	0.14	निजी भूमि	763	0.25	निजी भूमि
529/1	0.25	निजी भूमि	764	0.40	निजी भूमि
672	0.24	निजी भूमि	767	0.04	निजी भूमि
674	0.06	निजी भूमि	775	0.21	निजी भूमि
675	0.45	निजी भूमि	योग . .		55.68
533	0.45	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बहादुरगंज तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु,		
534	0.24	निजी भूमि			
535	0.48	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.		
536	0.07	निजी भूमि			
537	0.17	निजी भूमि	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		
554	0.46	निजी भूमि			
538	0.04	निजी भूमि	कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		
540	0.03	निजी भूमि			
546	0.02	निजी भूमि	दतिया, दिनांक 28 दिसम्बर 2013		
539	0.38	निजी भूमि			
550	0.06	निजी भूमि	क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		
660	0.06	निजी भूमि			
661	0.14	निजी भूमि	अनुसूची		
662	0.18	निजी भूमि			
663	0.26	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—		
664	0.30	निजी भूमि			
665	0.24	निजी भूमि	(क) जिला—दतिया		
669	0.28	निजी भूमि			
670	0.40	निजी भूमि	(ख) तहसील—बड़ौनी		
676	0.50	निजी भूमि			
678	0.99	निजी भूमि	(ग) ग्राम—छता		
703/1	0.60	निजी भूमि			
542	0.10	निजी भूमि	(घ) अर्जित क्षेत्रफल—1.17 हेक्टेयर.		
544	0.12	निजी भूमि			
545	0.23	निजी भूमि	खसरा नम्बर		
547	0.19	निजी भूमि			
548	0.10	निजी भूमि	रकबा		
549	0.18	निजी भूमि			
560	0.14	निजी भूमि	(हे. में)		
617	0.08	निजी भूमि			
618/2	0.05	निजी भूमि	(1)		
658	0.16	निजी भूमि			
659	0.23	निजी भूमि	(2)		
666	0.20	निजी भूमि			
667	0.19	निजी भूमि	(1)		
668	0.27	निजी भूमि			
671	0.42	निजी भूमि	(2)		
681/2	2.00	निजी भूमि			
703/2	0.05	निजी भूमि	(1)		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बहादुरगंज तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—बड़ौनी

(ग) ग्राम—छता

(घ) अर्जित क्षेत्रफल—1.17 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

845

0.09

847

0.03

848

0.11

(1)	(2)	कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
-----	-----	--

849	0.01
852	0.02
850	0.06
851	0.02
886	0.03
887	0.02
888	0.05
936	0.06
921	0.04
922	0.02
1088	0.03
926	0.02
927	0.04
928	0.02
929	0.03
937	0.04
938	0.04
1057	0.07
1059	0.03
1058	0.05
1087	0.03
1193	0.01
1089	0.02
1090	0.04
1091	0.06
1092	0.05
1191	0.01
1192	0.02

योग . . . 1.17

रीवा, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

पत्र क्र. 2428-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योथर
(ग) ग्राम—बड़ागांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.497 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
निजी भूमि	
713	0.032
748	0.108
754	0.087
795	0.082
990	0.102
1141	0.032
1836	0.007
2438	0.023
3741	0.024

योग . . . 0.497

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना दायीं तट नहर (महुअर नदी तक) आर.बी.सी. की छता माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2430-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्यौंथर
(ग) ग्राम—शिवपुरवा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.066 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
81	0.003
84/1	0.063
योग . .	<u>0.066</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्यौंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2432-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्यौंथर

- (ग) ग्राम—बुदामा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.188 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
6	0.007
10	0.100
11	0.012
31	0.069
योग . .	<u>0.188</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्यौंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2434-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्यौंथर
(ग) ग्राम—सहलोलवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.883 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
97	0.010
100	0.132
105	0.042
130	0.146
145/1	0.030
145/2	0.015
147	0.100

(1)	(2)	(1)	(2)
150	0.020	1233	0.01
203	0.030	1253	0.03
331	0.358	1254	0.03
योग . .	0.883	1255	0.02
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		1261	0.09
		1273	0.05
		1274	0.02
		1275	0.03
		1276	0.03
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		1277	0.02
		1278	0.02
		1279	0.02
क्र. 2436-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		1281	0.02
		1282	0.02
		1283	0.02
		1284	0.02
		1290	0.02
		1291	0.02
		1296	0.04
		1297	0.02
		1298	0.02
		1300	0.02
		1301	0.02
		1396	0.03
		1399	0.04
		1400	0.02
		1411	0.02
		1416	0.03
		1417	0.05
		1418/1	0.01
		1418/2	0.04
		1420	0.04
		1479	0.04
		1480	0.02
		योग (अ) . .	1.51
		(ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण	
		979	0.02
		1272	0.03
		योग (ब) . .	0.05
		महायोग (अ+ब) . .	1.56

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की पटेहरा सब-मार्डनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

(1)	(2)
222/2ग	0.065
222/1	0.162
223/2	0.324
218/2	0.162
218/4	0.149
218/1क	0.220
213/1क	0.084
214/3क	0.025
214/1	0.130
214/2	0.160
योग.	<u>2.513</u>

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-777-780-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील—अशोकनगर
(ग) ग्राम—जुग्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.513 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
131/1	0.123
132/2	0.016
133	0.001
131/2	0.020
134	0.233
142/1क	0.035
142/1ख	0.032
141	0.032
144	0.540

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरखेड़ा छज्जू बांध की बायीं तट की नहर के निर्माण हेतु स्थायी अर्जन.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-782-785-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील—अशोकनगर
(ग) ग्राम—अनन्तपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.000 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
184/3	0.103
185 में	0.032
186/मिन-2	0.020

(1)	(2)	(ग) ग्राम—जलालपुर	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.965 हेक्टेयर
186/मिन-1	0.012	सर्वे नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल
187/1क	0.014		(हे. में)
188/1	0.032	(1)	(2)
187/1	0.007	212	0.066
187/1ख	0.007	211, 216	0.204
187/2	0.014	210/1	0.185
176/2क	0.011	207/1	0.100
176/3	0.013	204/1	0.233
176/4	0.004	240/1 मिन 1	0.100
191	0.098	241/2	0.116
192/1	0.011	240/1 मि. 2	0.025
192/2	0.011	239 मिन 1	0.120
192/3	0.011	236/3	0.117
193	0.070	236/2	0.094
173/1	0.037	231/2	0.135
173/2	0.029	233	0.015
195/1क	0.054	402/2	0.300
137/2	0.112	433 मिन 1	0.155
137/1	0.123	योग. .	1.965
136	0.143		
134/2	0.032		
योग. .	1.000		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरखेड़ा छज्जू बांध की बायीं तट की नहर के निर्माण हेतु स्थायी अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, अशोकनगर एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-787-790-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील—अशोकनगर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरखेड़ा छज्जू बांध की बायीं तट की नहर के निर्माण हेतु स्थायी अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, अशोकनगर एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-792-796-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील—अशोकनगर

(ग) ग्राम—तूमेन	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.261 हेक्टेयर	421/1	0.040
	421/2	0.033
सर्वे नंबर	401	0.191
	414	0.135
(1)	408	0.108
(2)	412	0.259
93/1		योग. . 4.261
91		
84/1		
84/2		
83/3		
83/2		
85/3		
85/1		
85/2		
85/4		
85/5		
75/2ख		
72		
29/1		
19		
27		
14		
13		
5/3		
12		
8		
7		
5/4ख		
2		
297		
357/2 मिन-2		
312		
317		
295		
356 1 मिन		
355 1 मिन		
367		
424		
423		
422		
368		
394		
395		
396		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरखेड़ा छज्जू बांध की बायीं तट की नहर के निर्माण हेतु स्थायी अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग, अशोकनगर एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-797-800-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्द्वारायह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील—अशोकनगर
(ग) ग्राम—मढ़ी तूमेन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.637 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
205	0.050
207	0.023
210	0.100
211/2	0.100
213/मिन 2	0.090
213/1 मिन	0.010

(1)	(2)
312	0.005
311	0.100
310	0.060
320	0.040
309/मिन 1	0.080
322	0.025
306/1	0.110
306/2	0.110
305	0.020
329/1क	0.001
306/3	0.140
329/2 ख मिन 1	0.015
329/1 ख मिन 2	0.004
300/2 मिन 1	0.237
330/1	0.125
299/1	0.100
286/3	0.050
288	0.020
295	0.150
294/3	0.038
83/5	0.050
85/2	0.022
86	0.022
93/1	0.076
90	0.076
89/1	0.010
101/1	0.015
106	0.065
105	0.086
104	0.101
59	0.111
53/1	0.015
53/2	0.015
52	0.060
89/2	0.005
91/1	0.015
49/1	0.050
49/2	0.040
योग .	<u>2.637</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरखेड़ा छज्जू बांध की बायीं तट की नहर के निर्माण हेतु स्थायी अर्जन.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग, अशोकनगर एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्रनाथ शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13-मावन-465.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—गुना
(ख) तहसील—गुना
(ग) नगर/ग्राम—मावन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.627 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
228/1/5	0.209
228/1/6	0.209
228/1/7	0.209

योग : 0.627

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—स्पाइसेस बोर्ड ग्राम मावन बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय, अधिकारी (राजस्व) गुना तथा क्षेत्राधिकारी आफिसर इंचार्ज स्पाइसेस बोर्ड गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(ग) ग्राम—नयागांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—21.925 हेक्टेयर.

विदिशा, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 12-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम परियोजना की डूब क्षेत्र के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—त्योदा

(ग) ग्राम—रहमानपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.506 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
-----------	---

(1)	(2)
191/1/1	0.127
191/1/2	0.106
186/1	0.273

कुल योग . . 0.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बघरू मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम परियोजना की डूब क्षेत्र के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—त्योदा

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
-----------	---

(1)	(2)
137/1	0.376
137/2	0.805
138/1	0.199
138/2	1.922
139	1.045
142/1	1.442
142/2/क	0.418
142/2/ख	1.672
142/3	3.710
142/4	0.732
144	1.296
146/2	0.115
146/3, 147	0.157
148/1	0.635
148/2	0.635
148/3	1.269
149/1	0.073
149/2	1.433
150/2	0.648
153	0.539
313	0.679
162	0.799
163	0.667
164/1	0.115
164/2	0.115
168/1	0.143
168/2/क	0.071
168/2/ख	0.073
168/3	0.142

कुल योग . . 21.925

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बघरू मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम परियोजना की डूब क्षेत्र के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—त्यौंदा
- (ग) ग्राम—खिरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—15.182 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक अर्जित किये जाने वाला
अनुमानित क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
2, 3, 4, 5	1.839
9	0.042
10/1	0.401
10/2	0.366
12/1	0.731
12/2	0.732
13/1	0.491
13/2	0.492
14	0.251
15/2	0.851
16	0.262
17/2	0.909
24/2	0.350
15/1	0.852
17/1	0.909
18	0.105
21, 22	2.393
23	0.084
24/1	1.000
25	0.094
39/1	0.867
37	0.073
38	0.073
39/2	0.209
160	0.806

कुल योग . . 15.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बघरू मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम परियोजना की डूब क्षेत्र के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—त्यौंदा
- (ग) ग्राम—त्यौंदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—52.640 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक अर्जित किये जाने वाला
अनुमानित क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
760/1	0.827
760/2	0.802
751	0.337
749/1	1.359
749/3	0.432
970/1 क	0.096
970/1ख	0.165
970/1ग	0.515
970/1घ	0.374
970/2	0.500
974/1/1	0.627
974/1/3	0.627
974/1/2	0.627
974/1/4	0.752
974/2/2	0.230
974/2/1	0.836
975	0.800
976	2.515
977	0.158

(1)	(2)	(1)	(2)
990	0.362	834	0.105
991	1.568	874	0.752
992/2/1घ	0.304	885	0.177
992/2/2	0.539	887	0.700
992/2/3	1.000	890	0.418
993/1	0.506	891/2	0.480
992/1	0.596	891/1	0.147
993/2	0.210	892	0.679
955/1	0.423	893	0.288
955/2	0.020	895	1.944
956/1	0.300	405	0.136
956/2	0.200	407/2	0.141
956/3	0.200	400	0.012
957/1	0.099	394	0.058
957/2	0.098	408/1	0.021
957/3	0.098	408/2	0.021
957/4	0.098	410, 411	0.261
957/5	0.098	412/1	0.052
959/1	0.340	412/2	0.042
959/2	0.835	415	0.021
959/3	0.340	416	0.240
960/1	1.182	435/1	0.112
961	0.188	253	0.732
960/2	0.072	289/2	0.383
962/1	0.081	290/2	0.122
962/2	0.075	1184/3	0.645
962/3	0.091	1184/4	0.500
963	0.010	1184/5	0.440
964	0.052	1211/1	1.107
966/2	1.375	1211/2	1.108
821	0.073	1190/1/1	0.021
822	0.021	1190/1/2	0.397
823	0.230	1190/2	1.797
824	0.209	1190/3	1.986
825	0.105	1190/4ख	0.596
826/1क	0.026	1188/1, 1189/1	1.045
832/1क	0.340	1188/2, 1189/2	0.945
826/1ख	0.026	1193/2	2.100
832/1ख	0.339	1193/1	1.034
826/2	0.125	1193/3	1.158
827	0.052	1196/1	0.273
832/2	0.230	1196/2	0.981
828	0.428	1197/1	0.450
833	0.439	1197/2	0.679
		1196/3	0.752
		कुल योग . .	<u>52.640</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बघरूँ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.	(1)	(2)	
	212	1.202	
	220	0.136	
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.	222	0.146	
	223	0.084	
	224	0.042	
	225	0.084	
	226	0.105	
प्र. क्र. 16-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरूँ मध्यम परियोजना की डूब क्षेत्र के लिये आवश्यकता है:—	227/1, 227/2	0.115	
	228/1	0.026	
	228/2	0.026	
	229	0.084	
	232	0.010	
	233/1	0.094	
	233/2	0.094	
	247, 248	0.105	
	249	0.272	
(1) भूमि का वर्णन—	250	0.052	
(क) जिला—विदिशा	251	0.063	
(ख) तहसील—त्यौंदा	252/1	0.049	
(ग) ग्राम—सुमेरकासम	252/2	0.024	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—32.443 हेक्टेयर.	253/1/1	0.006	
सर्वे क्रमांक	अर्जित किये जाने वाला	253/1/2	0.005
	अनुमानित क्षेत्रफल	253/2	0.041
	(हेक्टेयर में)	276	0.052
(1)	(2)	277/2	1.033
215/1	0.048	102/1	0.115
244	0.042	102/2	0.115
236/2	0.047	103/1	0.523
169/2	0.385	103/2	0.523
158	0.627	106/1	0.569
153	0.392	106/2	0.152
154	0.219	107/1	0.465
155	0.209	107/2	0.099
156	0.105	57	1.045
238	0.138	59	0.032
239	0.136	60/2/2	1.961
240	0.073	61	0.178
241	0.042	62	0.146
205	0.272	63	0.178
207	0.021	64	0.240
208	0.052	65/1/क	0.650
209	0.021	65/2/क	0.152
210	0.105	65/2/ख	0.627
211	0.157	65/2/ग	0.836

(1)	(2)	(ग) ग्राम—पिपरिया दौलत	
		(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.318 हेक्टेयर.	
66/1	0.188	सर्वे क्रमांक	अर्जित किये जाने वाला
66/2	0.387		अनुमानित क्षेत्रफल
68	0.742		(हेक्टेयर में)
69	0.115	(1)	(2)
71	1.327	5/2	0.085
72, 73, 74, 75/1/1	0.886	45/1	0.028
75/1/2	0.484	45/2	0.029
75/2, 77, 78/2	2.091	45/3	0.028
76	0.397	49/1	0.173
78/1	0.115	50/1	0.230
79	0.544	47	0.401
80, 84	1.673	46/1	0.313
81	1.766	46/2	0.314
85/1	1.672	61/1/2	0.313
85/2	1.284	62/1	0.773
86/2	0.616	62/2/क	0.429
86/1	0.314	62/2/ख/2	0.152
87/1	0.917	64/1/1	0.034
87/2	0.003	64/1/2	0.068
91	1.275	64/1/3	0.034
योग . .	32.443	64/2	0.136
		64/3	0.125
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बघरू मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.		66	0.094
		72	0.136
		73	0.094
		74	0.094
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		75/2/1	0.131
		75/2/2	0.094
		75/3	0.262
		86/1	0.094
		86/2	0.105
		87	0.094
		88/1	0.146
		88/2	0.136
		89	0.105
		90	0.105
		91	0.136
		93	0.314
		95	0.073
		96/1	0.136
		97	0.243
		213/1	0.554
		214	0.256
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—विदिशा			
(ख) तहसील—त्योंदा			

(1)	(2)
120/2/2	0.349
124/2	0.65
125/2	0.084
126/2, 127/2	0.259
127/3	0.259
128/1	0.112
128/2	0.170
115	0.052
129	0.387
130	0.502
252/2	0.144
249/3	0.283
योग . .	<u>10.318</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बघरूँ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 3 जनवरी 2014

क्र. 92-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—उज्जैन

(ग) ग्राम—जीवनखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.275 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
54/17 min	0.030
54/17 min 1	0.015
9/1/2/1	0.230
योग . .	<u>0.275</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु जीवनखेडी तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.

(3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 94-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—खाचरौद
(ग) ग्राम—बेड़ावन्था
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.39 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
184	0.07
1160	0.06
1117/5	0.26
योग . .	<u>0.39</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन-जावरा मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद, जिला उज्जैन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(ग) ग्राम—कस्बा उज्जैन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.809 हेक्टर.

प्र. क्र. 99-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—खाचरौद

(ग) ग्राम—बिरियाखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.33 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

396/3

0.06

408

0.10

424/2

0.03

422

0.08

445

0.06

योग . . 0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन-जावरा मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद, जिला उज्जैन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 100-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—उज्जैन

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

3302

0.030

3303/3

0.180

3306

0.560

3307/2

0.030

3205/1

0.010

3212/1 m.

0.250

3291/1/2 m.

0.145

3291/1/2/2 m.

0.145

3289

1.350

3288/2 m.

0.157

3288/1 m.

0.468

3331

0.080

3286/2

0.020

3286/3

0.280

3237

0.410

3234/4

0.523

3236

0.030

3234/3

0.030

3235/1

0.490

3233/1 m., 3233/1 m.

0.060

3204/1/1 m.

0.146

3204/1/1 m. 5

0.169

3212/1

0.400

3211

0.430

3198/2

0.030

3206/1

0.180

3199/1

0.130

3176, 3175

0.490

3193

0.150

3183

0.050

3178/1

0.470

3163/4

0.167

3164

0.650

3179

0.040

3158

0.650

3162

0.600

3182

0.040

3156/1

0.021

3157/1

0.044

(1)	(2)
3156/2	0.042
3157/2	0.050
3154/2	0.033
3152 m.	0.177
3152 m.	0.393
3088/1/2, 3089/3, 3090/2	0.050
499/2	0.320
505/2	0.005
505/1	0.005
502	0.060
500	0.020
3091/1, 3091/2	0.010
501/2	0.080
490	0.070
489/2	0.259
441/1	0.146
440	0.081
441/2, 441/4,	0.223
511, 512	
510	0.430
488	0.018
431	0.290
418	0.350
404	0.210
411	0.060
405/2	0.080
406	0.090
405/1	0.087
400	0.350
401	0.020
3287	0.095
3303/1	0.050
3308/1	0.090
3303/2	0.210
3168	0.020
3165/1, 3166/1	0.100
3165/2, 3166/2	0.110
3191	0.020
योग . .	<u>14.809</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम कस्बा उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.

(3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. 58-59-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—राजगढ़
(ग) ग्राम—पाटनखुर्द एवं मुरारिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल —40.282 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—पाटनखुर्द	
183/1	0.069
183/2	0.070
194/2	0.146
197/2	0.076
199/2	0.097
198	0.750
199/1	0.097
184/1	0.180
191/2	0.186
190/2	0.228
192/2	0.019
195/3	0.012
196/3	0.054
184/2	0.150
190/3	0.228
191/3	0.186
192/2	0.019
196/1	0.055
195/1	0.013
185	0.200
191/1	0.185
184/3	0.149
195/2	0.013
196/2	0.055
193	0.063

(1)	(2)	(1)	(2)
200/1/1	0.075	473/14	0.990
200/1/2	0.075	473/16	0.500
200/2	0.130	475/1/1	0.076
217	0.038	475/2	0.930
218	0.228	475/3	1.170
219	0.089	योग . .	26.487
220	0.038		
221/1	0.012	ग्राम—मुरारिया	
222/1	0.046	193 में से	0.180
221/2	0.026	194/1 में से	0.759
223/1	0.050	194/2 में से	0.450
226/5	0.024	194/3	0.450
222/2	0.046	287/1	0.126
222/3	0.047	221	0.250
226/6	0.024	282 में से	0.465
226/1	0.070	286/1	0.100
229	0.417	286/2	0.100
230	0.025	286/3	0.100
473/10	0.253	287/2/1	1.998
470/2	0.500	301 में से	1.050
470/3	0.750	287/2/2/1	0.666
470/4	0.750	287/2/2/2	0.664
472/2	0.500	287/2/2/3	0.666
472/3	0.500	288/1 में से	0.820
473/1	0.379	289/1	0.848
473/2	0.379	289/3	0.390
473/3	0.379	289/2/1	0.316
473/4	0.253	289/2/2	0.317
473/5	0.253	289/4	0.630
473/6	0.253	290/1	0.600
443/15	0.500	290/2	0.110
473/7	0.379	291/2	0.100
473/8	0.379	291/1 में से	0.110
473/9	0.379	293/1	0.100
473/11	0.755	293/2	0.100
182 में से	6.425	294 में से	0.020
189	0.400	295/4	0.050
194/1	0.145	296	0.180
197/1	0.076	297 में से	0.540
227	1.250	299/1	0.100
228	0.190	299/2	0.100
190/1	0.227	300	0.340
475/4	0.202	योग . .	13.795
223/2	0.051	कुल योग . .	40.282
226/3	0.024		
223/3	0.050		
226/4	0.024	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—पाटनखुर्द	
223/4	0.051	तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु.	
226/2	0.024	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
225	0.126	(राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.	
473/12	0.755	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
473/13	0.500	इलैयाराजा टी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 5-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील—उदयपुरा

(ग) ग्राम—केवलारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.754 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	कुल रकबा (एकड़ में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
63/1/1	1.30	0.040
63/2/1	1.70	
64/1	7.50	0.162
66	1.89	0.125
137/1	6.00	0.243
138	11.98	0.206
139/2	3.31	0.081
139/3	3.31	0.081
139/1	9.32	0.202
140/2	4.11	0.105
148/1	5.44	0.121
140/3/2	4.00	
एवं	एवं	0.178
140/3/1	1.00	
148/2	5.00	0.121
154/1	2.97	0.150
170/1	9.46	0.259
170/2	9.46	0.186
170/3/1	5.03	
एवं	एवं	0.170
170/3/2	4.46	

(1)	(2)	(3)
172/1/2	1.08	
एवं	एवं	0.081
172/1/1	2.14	
172/2/1	0.07	
एवं	एवं	0.061
172/2/2	2.15	
172/3	3.22	0.061
174/1/1/1/1	1.37	
एवं	एवं	0.121
174/1/1/1/2	1.36	

कुल योग . . 2.754

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—जलाशय
नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी,
राजस्व बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

क्र. 7878-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—उज्जैन

(ग) ग्राम—पाण्याखेडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.751 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
150/3/1	0.005

(1)	(2)
152/1	0.018
156/1	0.069
167, 168, 169/238, 167/239, 169	0.430
170/मीन-2	0.380
174/3 व 4	0.320
228/4	0.160
228/5	0.180
173/6/1	0.045
228/3	0.050
173/1, 173/4, 173/5	0.094
कुल योग . .	<u>1.751</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन शहर में एम.आर.-5 मार्ग पर रेलवे समपार क्रमांक 29-ए उज्जैन भोपाल रेलखंड कि.मी. 57/38-40 पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

उज्जैन, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. 112-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—उज्जैन
 (ख) तहसील—उज्जैन
 (ग) ग्राम—मंगरोला
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.050 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
845	0.050
योग . .	<u>0.050</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु मंगरोला तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.

- (3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 13 जनवरी 2014

प्र. क्र. 13-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—विदिशा
 (ख) तहसील—नटेरन
 (ग) ग्राम—जामिनपुर
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.596 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
374/1	0.520
375/2	0.307
376/1	0.480
377/1	0.180
209/2	0.060
209/1	0.060
210	0.670
208/2	0.032
208/3	0.032
192/2	0.070
203	0.05
184/1/1	0.030

(1)	(2)	(1)	(2)
182/1	0.050	73/4	0.350
182/2	0.060	73/2	0.150
182/4	0.050	73/3	0.150
179/4	0.060	72/1	0.100
179/5	0.230	72/2	0.190
179/6	0.060	74	0.150
159/1	0.060	376	0.309
321/1	0.070	374	0.020
321/2	0.073	395/1	0.200
395/1	0.392	कुल योग . .	2.059
कुल योग . . 3.596			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—नटेरन
- (ग) ग्राम—बबचिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.059 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
69	0.440

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—नटेरन
- (ग) ग्राम—रजोदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.127 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
573/1	0.100
573/2	0.100

(1)	(2)
574/1/1/1	0.586
577	0.341
कुल योग . .	<u>1.127</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—तोफाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.200 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
76/2	0.090
101/2	0.020
76/4	0.090
कुल योग . .	<u>0.200</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-2012-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—सतपाड़ा हाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.755 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
220/1	0.105
622/2/1क	0.090
622/2/2ख	0.075
3/2	0.125
3/3	0.135
72	0.225
कुल योग . .	<u>0.755</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्र. A-4828-दो-2-71-2013.—श्री राकेश कुमार गुप्त, रजिस्ट्रार (एडमिनीस्ट्रेशन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-4830-दो-2-67-2013.—श्री नवीन कुमार सक्सेना, रजिस्ट्रार (ज्युडिशियल-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

क्र. A-4853-दो-2-58-2013.—श्री अनुपम श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-4860-दो-2-54-2013.—श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-4862-दो-2-15-2012.—श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को दिनांक 18 से 21 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4864-दो-2-53-2007.—श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 26 से 28 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4866-दो-2-36-2008.—श्री आर. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा को दिनांक 4 से 11 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12, 13, 14, 15 एवं 16 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7564-दो-2-71-2009.—श्री एच. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7567-दो-2-50-13.—श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7573-दो-2-44-2012.—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 26 से 29 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7587-दो-2-65-11.—श्री जे. पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-7589-दो-2-25-2013.—श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 18 से 19 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7591-दो-2-21-2005.—श्री उत्थास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 7 से 13 दिसम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री उत्थास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उत्थास बापट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्र. D-7700-दो-2-109-06.—श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. A-4910-तीन-10-42-75-(देवास-कन्नौद).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक ई/3271/तीन-10-42/75 (देवास-कन्नौद), दिनांक 2 अगस्त 2011 जहां तक कि उसका संबंध श्री भरत सिंह ओहरिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागली की श्रृंखला न्यायालय, कन्नौद से है, को एतद्वारा आगामी आदेश तक निरस्त किया जाता है।

No. A-4910-III-10-42-75-(Dewas-Kanod).—High Court Notification No. E/3271/III-10-42/75 (Dewas-Kannod), dated 2nd August 2011, so far as it relates to holding of Link Court of Shri Bharat Singh Ouhariya, Additional District & Sessions Judge Bagli to Kannod is hereby cancelled till further order.

Session Judge, Dewas in addition to his place of siting declared at Dewas shall also sit at Khategaon for 15 days in each month.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बिपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार. (डी.ई.)

क्र. A-4912-तीन-10-42-75-(देवास-खातेगांव).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री शिवबदन वर्मा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास अपने घोषित कार्यस्थल देवास के अतिरिक्त खातेगांव में भी प्रत्येक माह 15 दिवस बैठक करेंगे.

जबलपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. 1388-गोपनीय-2013-दो-3-100-2013.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश श्रीमती ऋतुश्री उईके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इन्दौर के न्यायालय के पंचम् अतिरिक्त न्यायाधीश, इन्दौर (प्रशिक्षु जज) का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन “श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता” पत्नी श्री विशाल गुप्ता करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

No. A-4912-III-10-42-75-(Dewas-Khategaon).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Shivbadan Verma, IInd Additional Distinct &

आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 17, 20 दिसम्बर 2013

क्र. 1380-गोपनीय-2013-II-2-36-2007.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश श्रम न्यायिक सेवा भर्ती नियम, 2006 के उप नियम 5 (ii) के तहत उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 1 (ए) 13-2013-ए-सोलह-भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2013 द्वारा सदस्य न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), औद्योगिक न्यायालय के पद पर अस्थायी तौर पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती किरण बाला पाठक, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रीवा.	रीवा	रीवा	रीवा	पदोन्नति पर, सदस्य न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), औद्योगिक न्यायालय, रीवा के पद पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

क्र. 316-स्था.सैट-2013.—श्री देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (सैट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) जबलपुर को दिनांक 24 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश अवधि में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (सैट) को वेतन भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

(3) उक्त अवकाश से लौटने पर श्री देवेश चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

रजिस्ट्रार महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.